

यूनिसन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

बनाम

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नोएडा

सिविल अपील संख्या 6788-6789/2005

फरवरी 13, 2009

(डॉ अरिजीत पसायत और डॉ मुकुंदकम शर्मा, जेजे.)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 5-ए-एसएसआई छुट अधिसूचना - किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम वाले सामान के सम्बन्ध में लाभ की अनुमती नहीं- निर्धारिती द्वारा यूटीएस और टीएसएन वाले स्टीकर चिपकाये गए आइटम- राजस्व "यूटीएस" और "टीएसएन" शब्दों को ब्रांड नाम के रूप में मानते हैं। अधिसूचना के लाभ को अस्वीकार करने वाले अन्य व्यक्ति- सीईएसटीएटी ने अपने निदेशक पर पृथक से अधिरोपित जुर्माने को छोड़ कंपनी पर लगाये गए शुल्क और जुर्माने की मांग को कायम रखा- निर्णित- विभिन्न निर्णयों में सांकेतिक कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं चुकि सीईएसटीएटी के निष्कर्ष अनिवार्य रूप से तथ्यात्मक हैं, हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है।

अपीलकर्ता अपने स्वयं के ब्रांड नाम 'क्रेमिका' में आईसक्रीम बनाने और बेचने के व्यवसाय में थे और एसएसआई छुट अधिसूचना का लाभ उठा रहे थे। यूनाइटेड टेली शोपिंग(यूटीएस) और टेली शोपिंग नेटवर्क (टीएसएन) को बेची गई वस्तुओं की फेक्ट्री से भेजने से पहले इन ग्राहकों के पर्यवेक्षाको द्वारा जाँच की जा रही थी और यूटीएस/टीएसएन वाले स्टिकर चिपकाए जा रहे थे। राजस्व ने इन शब्दों "यूटीएस" और "टीएसएन" को अन्य व्यक्तियों से सम्बंधित ब्रांड नाम के रूप में माना और छुट अधिसूचना के लाभ को अस्वीकार कर दिया। सीईएसटीएटी ने कंपनी पर लगाये गए शुल्क और जुर्माने की मांग को बरकरार रखा लेकिन इसके निदेशक पर पृथक से लगाये गए जुर्माने को रद्द कर दिया। व्यथित हो कर निर्धारिती ने अपील दायर की।

कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि :

सीईएसटीएटी के निष्कर्ष मूलतः तथ्यात्मक हैं। सीईएसटीएटी द्वारा अंकित तथ्यात्मक स्थिति और निर्णयों में इंगित कानून कि स्थिति को देखते हुए, हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। [पैरा 10][622-जी]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, त्रिची बनाम रुक्मणी पक्कवेल ट्रेडर्स 2004 (11) एससीसी 801, आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चंडीगढ़-1 बनाम महान डेयरिज, 2004 (11) एससीसी 798, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कलकत्ता बनाम एमके इन्वेस्टमेंट्स (पी) लिमिटेड और अन्य, 2005 (1)

एससीसी 526, रीज इलेक्ट्रोक्ंट्रोल्स (पी) लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त दिल्ली-1 2006 (6) एससीसी 213 आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चंडीगढ़-एल बनाम महान डेयरिज, 2004 (166) ईएलटी 23 (एससी) और पहावा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेंट्रल कमिश्नर एक्साइज, दिल्ली, 2005 (189) ईएलटी 257 (एससी) पर भरोसा किया गया।

यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम पालीवाल इलेक्ट्रिकल्स (पी) लिमिटेड और अन्य (1996) 3 एससीसी 407 का उल्लेख किया गया।

संदर्भित केस कानून

2004 (110) एसएससी 801	संदर्भित	मद संख्या 6
2004 (110) एसएससी 798	संदर्भित	मद संख्या 7
2005 (1) एसएससी 526	संदर्भित	मद संख्या 8
2006 (6) एसएससी 213	संदर्भित	मद संख्या 9
2004 (166) ईएलटी 23	संदर्भित	मद संख्या 9
(1996) 3 एसएससी 407	संदर्भित	मद संख्या 10
2005 (189) ईएलटी 257 (एससी)	संदर्भित	मद संख्या 11

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार - सिविल अपील 6788-6789/2005

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 01.03.2005 के सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली से अंतिम आदेश संख्या 250-251/05 बी।

अपीलकर्ताओं की ओर से जगजीत सिंह छाबड़ा।

एस वाशिम ए कादरी, अनिल कटियार, श्वेता गर्ग, आशीष गोपाल गर्ग, बी.के. प्रसाद और बी.वी. दलराम दास प्रतिवादी की ओर से।

न्यायलय का निर्णय पारित किया गया।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. इन अपीलों में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'सीईएसटीएटी') द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गयी है

मूल मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम वाले उनके द्वारा निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को मंजूरी दे रहे हैं।

2. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

एसएसआई छूट अधिसूचना जो एक एसएसआई इकाई द्वारा निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर छूट प्रदान करती है, यह प्रावधान करती है कि छूट किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाले सामान पर लागू नहीं होगी, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं। अधिसूचना के स्पष्टीकरण

में ब्रांड नाम को एक नाम या चिह्न के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कि एक प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लेखन जिसका उपयोग किसी व्यापार के दौरान कनेक्शन को इंगित करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में किया जाता है। निर्दिष्ट वस्तुओं और किसी व्यक्ति के बीच उस व्यक्ति की पहचान के संकेत के साथ या उसके बिना ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करना।

अपीलकर्ताओं के अनुसार वे आइसक्रीम निर्माता कूलर और पॉपकॉर्न बनाते हैं और एसएसआई छूट अधिसूचना का लाभ उठाते हैं और आइसक्रीम निर्माता को अपने ब्रांड नाम "क्रेमिका" के नाम से बेचते हैं और यूनाइटेड टेली शॉपिंग (संक्षेप में 'यूटीएस') और टेली शॉपिंग नेटवर्क (संक्षेप में 'टीएसएन') सहित विभिन्न ग्राहकों को इसे बेचते हैं और यूटीएस और टीएसएन को बिक्री के संबंध में इन ग्राहकों के पर्यवेक्षकों द्वारा सामान की जांच की जा रही थी। उनके कारखाने से भेजने से पहले और यूटीएस/टीएसएन वाले स्टिकर चिपकाए जा रहे थे और इन स्टिकर पर "चेक किया गया क्रम संख्या। इस स्टिकर को न हटाएं" शब्द अंकित हैं और विभाग ने यूटीएस और टीएसएन शब्दों को अन्य ब्रांड नाम के रूप में माना है और ने छोटे पैमाने पर छूट अधिसूचना का लाभ अस्वीकृत कर दिया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यूटीएस और टीएसएन शब्द ब्रांड नाम नहीं हैं, बल्कि विपणन कंपनियों के नाम के संक्षिप्त रूप हैं जो ब्रांड नाम के उपयोग के दायरे में नहीं आते हैं।

विभाग का रुख इस प्रकार रहा:

अपीलकर्ताओं द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया है कि उनके कारखाने के परिसर से निकासी से पहले उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर यूटीएस/टीएसएन के स्टिकर लगे होते हैं और एसएसआई छूट अधिसूचना में दिए गए ब्रांड नाम की परिभाषा के अनुसार, "ब्रांड नाम" का अर्थ कोई भी नाम, प्रतीक, मोनोग्राम है। लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लेखन जो उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं और ऐसे नाम का उपयोग करने वाले एक ही व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान संबंध को इंगित करता है और उत्पादों की पैकेजिंग पर उल्लिखित यूटीएस/टीएसएन शब्द यूटीएस के साथ व्यापार के दौरान संबंध को इंगित करते हैं और टीएसएन

प्रतिद्वंद्वी के रुख पर विचार करने के बाद सीईएसटीएटी ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

"सुनवाई के समय विद्वान सलाहकार द्वारा दिखाए गए नमूने के अवलोकन से पता चला कि स्टिकर में उल्लेख है कि इसे अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने के बाद लगाया गया है।"

वास्तव में स्टिकर इस प्रकार है:

टीएसएन - टेलीशोपिंग नेटवर्क
टीएसएन - यूनाइटेड टेलीशोपिंग
गुणवत्ता आपके द्वार पर

टीएसएन टेली शॉपिंग नेटवर्क यूटीएस यूनाइटेड टेलीशॉपिंग क्वालिटी आपके द्वार तदनुसार, सीईएसटीएटी ने अपीलकर्ता-कंपनी पर लगाए गए शुल्क और जुर्माने की मांग को बरकरार रखा, लेकिन कंपनी के निदेशक पर लगाए गए अलग से जुर्माने को खारिज कर दिया गया।

3. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ब्रांड नाम समान वस्तुओं पर लागू नहीं होते हैं। यह अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम है।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने फैसले का समर्थन किया और कहा कि भले ही तर्क के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि ब्रांड नाम अन्य व्यक्ति से संबंधित हैं, लेकिन इसका वास्तव में कोई परिणाम नहीं है।

5. विचाराधीन अधिसूचना इस प्रकार है:

"केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/97-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 मार्च, 1997 का सुपर सत्र, इसके द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट मंजूरी से छूट देता है, घरेलू उपभोग के लिए, इस अधिसूचना से जुड़े अनुबंध में निर्दिष्ट विवरण के उत्पाद शुल्क योग्य सामान (इसके बाद "निर्दिष्ट सामान" के रूप में संदर्भित), उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के उतने हिस्से से जो केन्द्रीय अनुसूची में निर्दिष्ट है, उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5), जैसा कि ऐसी मंजूरी के विरुद्ध उक्त तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट दर पर गणना की गई राशि से अधिक है।

3. मंजूरी के कुल मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मंजूरी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, अर्थात्: -

(ए) कोई भी मंजूरी, जो किसी अन्य अधिसूचना के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क (निकासी की मात्रा या मूल्य के आधार पर छूट के अलावा) से छूट प्राप्त है या जिस पर किसी अन्य कारण से कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं है;

(बी) किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाली कोई भी मंजूरी, जो नीचे दिए गए पैराग्राफ 4 के संदर्भ में इस छूट के अनुदान के लिए अयोग्य है:

(सी) निर्दिष्ट वस्तुओं की कोई भी मंजूरी जो निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के कारखाने के भीतर किसी भी निर्दिष्ट वस्तुओं के आगे के निर्माण के लिए इनपुट के रूप में उपयोग की जाती है। इनपुट के रूप में उपयोग की जाने वाली निर्दिष्ट वस्तुओं की ऐसी निकासी को उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से मुक्त माना जाएगा।

(डी) कपड़े की बुनाई के लिए या एथिलीन या प्रोपलीन के पॉलिमर से बने बोरे या बैग के निर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने के भीतर उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की पट्टियों की कोई मंजूरी को ।

4. इस अधिसूचना में निहित छूट निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम वाले सामान पर लागू नहीं होगी, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं:-

(ए) जहां निर्दिष्ट सामान, जो किसी मशीनरी या उपकरण या उपकरणों के घटकों या भागों की प्रकृति में हैं, को अध्याय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उक्त मशीनरी या उपकरण या उपकरणों के निर्माण में मूल उपकरण के रूप में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी जाती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के एक्स। निर्माता, जिनके मूल उपकरण के रूप में उपयोग के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की मंजूरी का कुल मूल्य एक वित्तीय वर्ष में तीस लाख रुपये से अधिक नहीं है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय ऐसे उपयोग के संबंध में एक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त नियमों के अध्याय X में;

(बी) जहां माल पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग या राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग विकास निगम या राज्य लघु उद्योग निगम का ब्रांड नाम या व्यापार नाम है;

5. स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए:-

(ए) "ब्रांड नाम" या "व्यापार नाम" का अर्थ एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम होगा, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं, यानी एक नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लेखन जिसका उपयोग ऐसे निर्दिष्ट सामानों के संबंध में इंगित करने के उद्देश्य से किया जाता है, या इस तरह से ऐसे निर्दिष्ट सामानों और उस व्यक्ति की पहचान के संकेत के साथ या उसके बिना ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान संबंध को इंगित करने के लिए किया जाता है।

(बी) जहां किसी निर्माता द्वारा निर्मित निर्दिष्ट सामान पर किसी अन्य निर्माता या व्यापारी का ब्रांड नाम या व्यापार नाम होता है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं, ऐसे निर्दिष्ट सामान को केवल इस तथ्य के कारण उसके द्वारा निर्मित होने से इनकार नहीं किया जाएगा। अन्य निर्माता या व्यापारी।"

6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, त्रिची बनाम रुक्मिणी पक्कवेल ट्रेडर्स

(2004 (11) एससीसी 801) में इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

5. ट्रिब्यूनल तब इस आधार पर आगे बढ़ता है कि छूट से इनकार केवल तभी किया जा सकता है जब ट्रेड मार्क या ब्रांड नाम का उपयोग उसी सामान के संबंध में किया जाता है जिसके लिए ट्रेड मार्क पंजीकृत है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में हमें डर है कि ट्रिब्यूनल ने कुछ ऐसा किया है जो कानून में करने की अनुमति नहीं है। यह स्थापित कानून है कि छूट अधिसूचनाओं का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। उनकी व्याख्या उनके अपने शब्दों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी अन्य अधिसूचना के शब्दों का किसी विशेष अधिसूचना के अर्थ में कोई लाभ नहीं है . इस अधिसूचना के खंड 4 और स्पष्टीकरण (यहां ऊपर दिए गए) यह स्पष्ट करते हैं कि छूट लागू नहीं होगी यदि निर्दिष्ट सामान (यानी सुगंधित सुपारी) पर किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांड या व्यापार नाम है। न तो अधिसूचना के खंड 4 में और न ही स्पष्टीकरण IX में यह प्रावधान किया गया है कि निर्दिष्ट सामान उस सामान के समान या समान होना चाहिए जिसके लिए ब्रांड नाम या व्यापार नाम पंजीकृत है। ट्रिब्यूनल ने, उपरोक्त तर्क को अपनाते हुए, प्रभावी ढंग से अधिसूचना शब्दों में जोड़ा है " समान सामान के संबंध में ब्रांड नाम या व्यापार नाम"। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है

| यह देखा जाना चाहिए कि कोई अपंजीकृत ब्रांड नाम या अपंजीकृत व्यापार नाम हो सकता है | ये किसी विशेष सामान के संबंध में नहीं हो सकते हैं। यहां तक कि अगर किसी अपंजीकृत ब्रांड नाम या व्यापार नाम का उपयोग किया जाता है, तो भी छूट समाप्त हो जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक ब्रांड नाम या व्यापार नाम का उपयोग किया जाता है, तब तक छूट समाप्त हो जाएगी, भले ही उपयोग उसी सामान पर हो जिसके लिए चिह्न पंजीकृत है।

6. ट्रिब्यूनल ने यह भी माना था कि अधिसूचना के तहत उपयोग "ऐसे ब्रांड नाम" का होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने माना है कि "ऐसे ब्रांड नाम" शब्द दर्शाते हैं कि उसी ब्रांड नाम या व्यापार नाम का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने माना है कि अगर कोई मतभेद है तो छूट खत्म नहीं होगी। हमें डर है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में ट्रिब्यूनल ने स्पष्टीकरण IX को नजरअंदाज कर दिया है। स्पष्टीकरण IX यह स्पष्ट करता है कि ब्रांड नाम या व्यापार नाम का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार नाम (चाहे पंजीकृत हो या नहीं), यानी एक नाम या चिह्न, कोड नंबर, डिज़ाइन नंबर, ड्राइंग नंबर, प्रतीक, मोनोग्राम होगा , लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत

शब्द या लेखन। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी ब्रांड नाम या व्यापार नाम के हिस्से का उपयोग, जब तक यह व्यापार के दौरान किसी संबंध का संकेत देता है, व्यक्ति को अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त करने से वंचित करने के लिए पर्याप्त होगा। इस मामले में, माना जाता है कि ब्रांड नाम या व्यापार नाम समूह के संस्थापक की तस्वीर के साथ "एआरआर" शब्द है। केवल इसलिए कि पंजीकृत व्यापार चिह्न पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है, उत्तरदाताओं को खंड 4 से बाहर नहीं ले जाता है और उन्हें अधिसूचना के लाभ के लिए पात्र नहीं बनाता है।"

7. इसी प्रकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-1 बनाम महान डेयरीज (2004 (11) एससीसी 798) पैरा 6 और 8 में इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

"6. हमने आज सीसीई बनाम रुक्मणि पक्कवेल ट्रेडर्स (2004 (11) एससीसी 801) में एक फैसला सुनाया है, जिसमें हमने समान शब्दों वाली एक अन्य अधिसूचना के संबंध में कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माल जिस पर व्यापार का नाम है या नहीं उपयोग किया जाने वाला चिह्न वही है जिसके संबंध में व्यापार चिह्न पंजीकृत है।"

भले ही सामान अलग-अलग हो, जब तक किसी अन्य कंपनी का व्यापार नाम या ब्रांड नाम उपयोग किया जाता है, अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा, हमारे विचार में, एक बार किसी व्यापार नाम या ब्रांड नाम का उपयोग किया जाता है तो केवल अतिरिक्त शब्दों का उपयोग पार्टी को अधिसूचना के लाभ का दावा करने में सक्षम नहीं करेगा।

8. यह स्थापित कानून है कि किसी अधिसूचना के लाभ का दावा करने के लिए, किसी पार्टी को अधिसूचना की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि अधिसूचना के शब्दों पर लाभ उपलब्ध नहीं है तो अधिसूचना के शब्दों को बढ़ाकर या अधिसूचना में शब्द जोड़कर लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है | ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले को रुक्मणि पक्कवेल ट्रेडर्स बनाम सीसीई (1999 (109) ईएलटी 204 (सीईजीएटी) में दिए गए फैसले पर आधारित किया है। हमने पहले ही उस मामले में फैसले को खारिज कर दिया है। इस मामले में भी हम मानते हैं कि का फैसला ट्रिब्यूनल टिकाऊ नहीं है। तदनुसार इसे रद्द किया जाता है।"

8. इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता बनाम एमके इन्वेस्टमेंट्स (पी) लिमिटेड और अन्य (2005 (1) एससीसी 526) इस न्यायालय ने कानून में स्थिति इस प्रकार बताई:

7. मौजूदा मामले में विवाद यह है कि क्या उत्तरदाता जो अपने ब्रांड नाम "पेलिकन" के तहत प्लाइवुड के निर्माता हैं, ने खुद को छोटे पैमाने पर छूट अधिसूचना संख्या 175/86-सीई के लाभ से वंचित कर दिया है। अपने उत्पादों पर उनके ब्रांड नाम के साथ "मेरिनो" दर्शाने वाले लोगो का उपयोग करके। अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या चिह्नों या शिलालेखों को मेसर्स मेरिनोप्लाई एंड केमिकल्स लिमिटेड के ब्रांड नाम के रूप में माना जाना चाहिए और इसके अंतर्गत आएगा जैसा कि विभाग ने तर्क दिया है, खंड 7 की शरारत अधिसूचना के स्पष्टीकरण VIII के साथ पढ़ी जाती है। खंड 7 इस प्रकार है:

"इस अधिसूचना में निहित छूट निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जहां एक निर्माता निर्दिष्ट वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम (पंजीकृत या नहीं) के साथ चिपकाता है जो इस अधिसूचना के तहत छूट के अनुदान के लिए पात्र नहीं है।"

खंड 7 का स्पष्टीकरण VIII इस प्रकार है:

"ब्रांड नाम' या 'व्यापार नाम' का मतलब एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम होगा, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, यानी एक नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लेखन जिसका उपयोग किया जाता है ऐसे निर्दिष्ट माल के संबंध में, ऐसे निर्दिष्ट माल और उस व्यक्ति की पहचान के किसी भी संकेत के साथ या उसके बिना ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान संबंध को इंगित करने के लिए, या ऐसा इंगित करने के लिए।"

8. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री जीई वाहनवती ने प्रस्तुत किया कि विवादित माल में मेसर्स मेरिनोप्लाई एंड केमिकल्स लिमिटेड का पंजीकृत लोगो "मेरिनो" शामिल था और उसके स्वामित्व में था। इस प्रकार यह एक स्पष्ट मामला था जहां विवादित माल को स्वीकार्य रूप से चिपकाया गया था। दूसरे व्यक्ति का पंजीकृत लोगो/व्यापार चिह्न जो एसएसआई छूट के लिए पात्र नहीं है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, सीईजीएटी ने यह न समझकर गलती की कि अधिसूचना संख्या 175/86-सीई के खंड 7 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, यह पर्याप्त है कि उत्पाद में किसी अन्य अपात्र व्यक्ति का ट्रेडमार्क/लोगो शामिल था जो पूरी तरह से संतुष्ट था। वर्तमान मामला और क्या उत्पाद में निर्माता का ब्रांड नाम/व्यापार

नाम/लोगो भी शामिल हैं, ऐसी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

आगे बहस करते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई स्पष्टीकरण VIII की व्याख्या कानून और तथ्य में सही प्रतीत नहीं होती है। यह जरूरी था कि अपने स्वयं के उत्पादों पर मेसर्स मेरिनोप्लाई एंड केमिकल्स लिमिटेड से संबंधित पंजीकृत लोगो "मेरिनो" का उपयोग करके, यहां पहले प्रतिवादी, मेसर्स एमके इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने उक्त उत्पादों के बीच संबंध को इंगित करने के उद्देश्य को पूरा किया। और लोगो स्वामी ताकि व्यापार को प्रभावित किया जा सके और इसलिए, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, स्पष्टीकरण VIII के प्रावधान पूरी तरह से संतुष्ट थे। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने यह भी प्रस्तुत किया कि कर कानून में अपवाद या छूट प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिए और यह छूट अधिसूचना में निर्धारित शर्तों की अनदेखी करने के लिए अदालत या न्यायाधिकरण के लिए खुला नहीं है।

9. अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

1. बीएचईएल सहायक एसोसिएशन। वी. सीसीई (1990 (49) ईएलटी 33 (मैड)

2. सीसीई बनाम रुक्मणि पक्कवेल ट्रेडर्स (2004 (11) एससीसी

3. सीसीई बनाम महान डेयरीज़ (2004 (11) एससीसी 798)

4. सीसीई बनाम भल्ला एंटरप्राइजेज (2004 (173) ईएलटी 225)

15. हमने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित सामान्य आदेश का अध्ययन किया है। हमारे विचार में, ट्रिब्यूनल ने इस बात को न समझकर गलती की है कि अधिसूचना संख्या 175/86-सीई के खंड 7 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, यह पर्याप्त है कि उत्पाद में किसी अन्य अपात्र व्यक्ति का ट्रेडमार्क/लोगो शामिल था जो पूरी तरह से संतुष्ट था। तत्काल मामला और क्या उत्पाद में निर्माता का ब्रांड नाम/व्यापार नाम/लोगो भी शामिल है, ऐसी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई स्पष्टीकरण VIII की व्याख्या कानून और वास्तव में सही प्रतीत नहीं होती है। यह जरूरी था कि मेसर्स मेरिनोप्लाई एंड केमिकल्स लिमिटेड से संबंधित पंजीकृत लोगो "मेरिनो" का अपने उत्पाद पर उपयोग करके मेसर्स एमके इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड उक्त उत्पादों और लोगो मालिक के बीच संबंध दर्शाने के उद्देश्य को पूरा करे ताकि व्यापार को प्रभावित करने के लिए और इसलिए, जहां तक मामले का संबंध है, स्पष्टीकरण VIII के प्रावधान पूरी तरह से संतुष्ट थे। इसके विपरीत ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष, हमारी राय में, गलत है और रद्द किये जाने योग्य है।"

9. रीज़ इलेक्ट्रोक्ंट्रोल्स (पी) लिमिटेड बनाम केद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-1 (2006 (6) एससीसी 213) से उदत पद को इस प्रकार दोहराया गया:

"8. जहां तक गैर-पात्रता के संबंध में विचारों का सवाल है, इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में व्यक्त किए गए विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।"

9. केद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-1 बनाम महान डेयरीज़ [2004 (166) ईएलटी 23 (एससी)] में इसे (पैरा 6 में) इस प्रकार नोट किया गया था:

"हमने आज केद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, त्रिची बनाम रुक्मणि पक्कवेल ट्रेडर्स - 2004 (165) ईएलटी 481 (एससी) (सिविल अपील संख्या 3227-3228/1998) में एक फैसला सुनाया है, जिसमें हमने एक अन्य अधिसूचना के संबंध में फैसला सुनाया है। समान शब्द कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस सामान पर व्यापार नाम या चिह्न का उपयोग किया जाता है वह वही है जिसके संबंध में व्यापार चिह्न पंजीकृत है। भले ही सामान तब तक भिन्न हो जब तक व्यापार नाम या ब्रांड नाम किसी अन्य का हो कंपनी का उपयोग किया जाता है तो अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा, हमारे विचार में, एक बार व्यापार नाम या ब्रांड नाम का उपयोग किया जाता है तो केवल अतिरिक्त शब्दों का

उपयोग पार्टी को अधिसूचना के लाभ का दावा करने में सक्षम नहीं करेगा।"

10. युनियन ऑफ इंडिया बनाम पालीवाल इलेक्ट्रिकल्स (पी) लिमिटेड और अन्य [(1996) 3 एससीसी 407] में यह नोट किया गया था (पैरा 10 और 11 में) इस प्रकार है:

"10. हमारी राय है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत छूट अधिसूचना को चुनौती की जांच करते समय, उपरोक्त निर्णयों में टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि आम तौर पर छूट अधिसूचना और शर्तों और उसमें निर्धारित शर्तें सार्वजनिक हित और सार्वजनिक राजस्व की रक्षा के लिए विकसित सरकार की नीतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अनुच्छेद 14 के आधार पर उन्हें चुनौती देने वाले व्यक्ति पर बहुत भारी बोझ पड़ता है। जब तक अन्यथा स्थापित न हो, अदालत को यह मानना चाहिए कि उक्त संशोधन था, केंद्र सरकार ने उक्त अधिसूचना के कामकाज के आधार पर अपनी नीति (अधिसूचना के तहत) को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पाया और व्यक्तियों को रियायत का अनुचित लाभ लेने से रोकने के लिए ऐसा संशोधन आवश्यक पाया गया। वास्तव में, इस मामले में, संशोधन अधिसूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक नोट इतने सारे शब्दों में ऐसा कहता है। यदि आवश्यक हो, तो न्यायालय केंद्र सरकार से संशोधन के

पीछे के कारणों को स्थापित करने के लिए कह सकता था। (उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा।) यह ध्यान में रखना भी उतना ही आवश्यक है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार बताया गया है, कि आर्थिक और कराधान क्षेत्र में, विधायिका को एक बड़े अक्षांश की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालतों को आरके गर्ग बनाम भारत संघ [1981 (4) एससीसी 675] में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखना चाहिए: (एससीसी पीपी. 690-91, पैरा 8)

"समानता का एक और नियम महत्व यह है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को भाषण, धर्म आदि की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए। यह होम्स, जे से कम किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कहा गया है कि विधायिका को कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए जोड़ों में, क्योंकि इसे जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो किसी भी सिद्धांत या स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूले के माध्यम से समाधान की अनुमति नहीं देते हैं और यह आर्थिक मामलों से निपटने वाले कानून के मामले में विशेष रूप से सच है, जहां, समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इससे निपटने की आवश्यकता है, विधायिका को जोड़ों में अधिक से अधिक खेल की अनुमति देनी होगी। न्यायालय को अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विनियमन के क्षेत्र में विधायी निर्णय को न्यायिक सम्मान देने के लिए अधिक इच्छुक महसूस करना चाहिए जहां मौलिक मानवाधिकार शामिल हैं।

इस चेतावनी को मोरे बनाम डौड [354 यूएस 457 (1957)] की तुलना में कहीं अधिक प्रसन्नतापूर्वक व्यक्त नहीं किया गया है, जहां फ्रैंकफर्टर, जे. ने अपनी अनूठी शैली में कहा था: "उपयोगिताओं, कर और आर्थिक विनियमन मामलों में, विधायी निर्णय के प्रति न्यायिक सम्मान नहीं तो न्यायिक आत्म-संयम के अच्छे कारण हैं। आखिरकार विधायिका की सकारात्मक ज़िम्मेदारी है। न्यायालयों के पास केवल विध्वंस करने की शक्ति है, पुनर्निर्माण करने की नहीं। जब इन्हें आर्थिक विनियमन की जटिलता को जोड़ा जाता है, तो अनिश्चितता, गलती का दायित्व, विशेषज्ञों का हैरान करने वाला संघर्ष, और कितनी बार न्यायधिशो को घटनाओ से अनदेखा किया गया है, आत्म सीमा को न्यायिक ज्ञान और संस्थागत अनिश्चितता, त्रुटि के प्रति दायित्व, विशेषज्ञों के हतप्रभ करने वाले संघर्ष और घटनाओं द्वारा न्यायाधीशों द्वारा खारिज की गई संख्या की संख्या में जोड़ दिया जाता है - तो आत्म-सीमा को न्यायिक ज्ञान और संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता के मार्ग के रूप में देखा जा सकता है।"

अदालत को हमेशा याद रखना चाहिए कि 'कानून व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित है, कि आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, कि कई समस्याएं एकल और आकस्मिक हैं, कि कानून अमूर्त प्रस्ताव नहीं हैं और अमूर्त इकाइयों से संबंधित नहीं हैं और नहीं होने चाहिए अमूर्त समरूपता द्वारा मापा गया' कि सटीक ज्ञान और उपचार का अच्छा अनुकूलन हमेशा संभव नहीं होता है और यह निर्णय काफी हद तक

अल्प और अट्याख्यायित अनुभव पर आधारित एक भविष्यवाणी है। 'विशेष रूप से आर्थिक मामलों में प्रत्येक कानून अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य है और यह प्रयोग या जिसे कोई परीक्षण और त्रुटि पद्धति कह सकता है, पर आधारित है और इसलिए यह सभी संभावित स्थितियों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है या सभी संभावित दुरुपयोगों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। जटिल प्रयोगात्मक आर्थिक विधान में असंवेदनशीलता और असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन केवल उसी आधार पर इसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के सचिव ने बताया है, अदालतें ऐसा नहीं कर सकतीं। कृषि बनाम सेंट्रल रोइंग रिफाइनिंग कंपनी [94 एल एड 381: 338 यूएस 604 (1950)] को ऐसी क्रूरताओं और असमानताओं से राहत के लिए न्यायाधिकरण में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यहां तक की दुरुपयोग की भी संभावना हो सकती है, लेकिन वह भी अपने आप में कानून को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी विधायिका के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किसी दैवीय विवेक के कारण उसके द्वारा बनाए गए कानून में विकृतियां और दुरुपयोग हो सकते हैं। जो इसके प्रावधानों के अधीन हैं और ऐसी विकृतियों और दुरुपयोगों के खिलाफ प्रावधान करते हैं। वास्तव में, इसके निर्माण में चाहे कितनी भी बड़ी सावधानी बरती गई हो, ऐसे कानून की कल्पना करना मुश्किल है जो विकृत मानवीय प्रतिभा द्वारा दुरुपयोग करने में सक्षम नहीं है। इसलिए न्यायालय को ऐसे कानून की

संवैधानिकता को उसके प्रावधानों की व्यापकता के आधार पर तय करना चाहिए, न कि इसकी अशिष्टताओं या असमानताओं या दुरुपयोग की संभावनाओं के आधार पर, विधायिका हमेशा कदम उठा सकती है और उपयुक्त संशोधन कानून बना सकती है। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण का सार है जिसे जटिल आर्थिक मुद्दों से निपटने में विधायिका को मार्गदर्शन और प्रेरित करना चाहिए।"

11. यही सिद्धांत छूट अधिसूचनाओं के मामले में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि उक्त शक्ति अधिनियम का अभिन्न अंग है और इसका उपयोग अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए-बेशक, शर्त के अधीन यह अधिसूचना अधिनियम और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है | (पीजे ईरानी बनाम मद्रास राज्य देखें [(1962) 2 एससीआर 169])"

11. पाहवा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली [2005 (189) ईएलटी 257 (एससी)] में इसे पैरा 3 में इस प्रकार रखा गया था:

"अधिसूचना के पैराग्राफ 4 और स्पष्टीकरण IX को इस न्यायालय द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम रुखमणी पक्कवेल ट्रेडर्स, 2004 (165) ईएलटी 481 के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ बनाम मैकज़ान डेयरीज़, 2004 (166) ईएलटी 23 इन दोनों निर्णयों में इस

न्यायालय ने माना कि अधिसूचना के स्पष्टीकरण IX के साथ पढ़े गए पैराग्राफ 4 को उस तरीके से नहीं समझा जा सकता जैसा कि निर्धारिती द्वारा तर्क दिया गया है, अर्थात्, व्यापार चिह्न/व्यापार नाम के मालिक के लिए इसका उपयोग करना आवश्यक है। निर्धारिती द्वारा निर्मित निर्दिष्ट माल के संबंध में माल। हमें उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय के तर्क से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता। स्पष्टीकरण IX के साथ पढ़ी गई अधिसूचना का खंड 4 स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों को छूट के लाभ से वंचित करता है जो अपने माल के संबंध में किसी और के नाम का उपयोग या तो संकेत देने के इरादे से या इस तरह से करते हैं ताकि निर्धारिती के माल और के बीच संबंध का संकेत मिल सके। ऐसा अन्य व्यक्ति. ट्रेड मार्क के मालिक के लिए किसी विशेष सामान के संदर्भ में नाम या चिह्न का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छूट अधिसूचना का उद्देश्य न तो व्यापार चिह्न/व्यापार नाम के मालिकों और न ही उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाना था। ये ऐसे विचार हैं जो ट्रेड मार्क्स अधिनियम के तहत उल्लंघन/कार्रवाई से उत्पन्न विवादों से संबंधित मामलों में प्रासंगिक हैं । अधिसूचना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से केवल उन उद्योगों को लाभ देना है जिन्हें अन्यथा ब्रांड नाम का लाभ नहीं मिलता है। करदाता की ओर से उपस्थित वकील द्वारा उद्धृत निर्णय ट्रेड मार्क विवादों से जुड़े निर्णयों से संबंधित हैं और परिस्थितियों में उचित नहीं हैं।"

13. ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष ऐसा कोई रुख नहीं अपनाया गया। महान डेयरी के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसके मद्देनजर किसी भी स्थिति में ट्रिब्यूनल को याचिका पर विचार करना होगा। महान डेयरी के मामले (सुप्रा) में इसे इस प्रकार देखा गया:

"9. हालाँकि, यह आग्रह किया गया था कि उत्तरदाताओं ने मार्क "महान टेस्ट मेकर" के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। हम स्पष्ट करते हैं कि यदि और जब वे अपना मार्क पंजीकृत करवा लेते हैं तो वे बोर्ड के अनुसार अधिसूचना के लाभ के हकदार बन जाएंगे। परिपत्र क्रमांक 88/88, दिनांक 13.12.1988।"

10. CESTAT के निष्कर्ष अनिवार्य रूप से तथ्यात्मक हैं, अतः हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। CESTAT द्वारा नोट की गई तथ्यात्मक स्थिति और ऊपर बताई गई कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपीलें खारिज की जाती हैं।

नोट:- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीलम शर्मा, आर.जे.एस., अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या-02, नीम का थाना (राज.) द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण:- यह निर्णय पक्षकार के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मानी होगा।